संपादकीय जागरण

सोमवार, 28 मई, 2018 : ज्येष्ठ शुक्ल 14 वि. 2075

मानसिक दृढ़ता सबसे मजबूत हथियार है

आसान नहीं आखिरी साल की राह

प्रशांत मिश्र

इसमें कोई शक नहीं कि मोदी की लोकप्रियता और शाह के चुनावी प्रबंधन का कोई सानी नहीं, लेकिन भाजपा के लिए चुनावी चुनौती मुश्किल होगी

तीन दशक से आ रहे खंडित जनादेश के बाद मई 2014 में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। जनता के इस समर्थन और विश्वास को सलाम करते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की चौखट पर अपना माथा रखा था तभी एक नए युग की शुरुआत का अहसास हुआ था। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। भाजपा के कई राजनेता भौंचक थे तो विपक्ष ने इसे नाटक माना था, लेकिन भाजपा के कोर मतदाता और जनता जनार्दन ही नहीं विपक्षी दलों के वोटरों ने महसूस किया था कि पहली बार कोई ऐसा नेता आया है जो लोकतंत्र में पूरी तरह विश्वास करता है और अंतिम आदमी तक सरकार को पहुंचा सकता है। पिछले चार साल में उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिये इस विश्वास को और मजबूत कर दिया। मोदी पर यह भरोसा बढ़ता गया और भाजपा की झोली भरती गई। एक के बाद एक हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, असम, त्रिपुरा तक भाजपा व राजग शासित राज्यों की सीमा का विस्तार होता गया और विपक्ष लगातार बौना होता चला गया। हां, इस बीच बिहार व दिल्ली जैसे चुनावों में झटका भी लगा और उसके साथ ही यह अहसास भी कराया गया कि विकास की लहर के बावजूद जातिगत राजनीति का अंत अभी नहीं हुआ है और न ही गठबंधन का। ऐसे में जब सरकार पांचवें साल में प्रवेश कर चुकी है तो कदम बहुत संभल कर रखने होंगे।

मोदी जनता के मर्म को पहचानते हैं और इसका भान भी रखते हैं कि कब कौन सी दवा देनी है। भ्रष्टाचार उनका सबसे बड़ा चुनावी नारा था और इसीलिए पहली कैबिनेट बैठक में कालेधन पर हमला किया था। जनता को समग्रता से विकास की राह में जोड़ने के लिए जनधन जैसी योजनाओं को भी परवान चढ़ाया था। धीरे-धीरे उन्होंने कड़वी दवा देनी शुरू की। नोटबंदी जैसी कड़वी दवा दी तो विपक्ष को लगा जैसे हाथ में बटेर आ गया। खुलकर उसका विरोध किया, जुलूस निकाले, लेकिन जनता में यह दांव फिट बैठा। जिस नोटबंदी के सहारे सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश जीतने का आसरा लगाए बैठी थी, वहां जनता ने भाजपा को सिर आंखों पर बिठा लिया। मोदी ने फिर से एक कड़वी दवा दी- जीएसटी। यह फिक्र किए बगैर कि इसके दायरे में भाजपा का कोर वोटर आता है। विपक्ष ने फिर से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात में विफलता मिली। हां, जनता ने थोड़ा सतर्क जरूर किया कि कड़वा के बाद मीठा और मीठे के बाद कड़वा तो ठीक है, लेकिन लगातार सख्ती परेशानी पैदा करती है। सरकार और पार्टी के स्तर पर भी इसका अहसास हुआ हो, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगले एक साल में सुधार के एजेंडे के बजाय कल्याणकारी योजनाओं की बहार की संभावना जताई जा रही है।

सत्तापक्ष और विपक्ष के बोल हमेशा एक से होते हैं, इससे जुदा कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में। यही कारण है कि जनता इनके दावों व आरोप-प्रत्यारोप को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। जनता वही मानती है जो वह देखती है। वह उसी की सुनती है जो विश्वसनीय हो। वह वाकया भी हर किसी को याद है जब सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया था और सुरक्षित अपनी सीमा में लौट आई थी। देश में जश्न मना था, लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं व दलों ने सेना के पराक्रम पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि उसका हश्र देखने के बाद सबने चुप्पी साध ली। निचोड़ यह है कि पिछले चार साल में नरेंद्र मोदी के फैसलों पर दलों ने सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन जनता ने खुलकर उनका स्वागत किया। राजनीतिक मोर्चों पर समर्थन देकर इसका इजहार भी किया। यह और बात है कि दिल्ली और बिहार ने आगाह भी किया। दिल्ली में जनता ने एक ऐसी पार्टी को मौका दिया था जो लीक से हटकर दिख रही थी। बिहार में गठबंधन की ताकत सामने आई थी। दिल्ली में अब उस नई पार्टी का नकाब हट चुका है।

पिछले दिनों एक और बड़ा बदलाव दिखा.. जनेऊ राजनीति शुरू हुई। हिंदुत्व को राजनीति में सांप्रदायिकता से जोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का जनेऊ दिखाने लगी। राहुल खुद को शिवभक्त करार देने लगे और कांग्रेस जनेऊधारी ब्राह्मण का नारा देने लगी। पिछले एक डेढ़ वर्षों में राहुल ने जितने मंदिरो मठों का दर्शन किया वह पार्टी के लिए ऐतिहासिक था। इन्हीं दो-तीन वर्षों में इफ्तार की राजनीति भी कम हो गई।

खैर, अगले लोकसभा चुनाव का नगाड़ा अभी से बजने लगा है। विपक्ष में गोलबंदी का नारा शुरू हुआ है। नारा इसलिए, क्योंकि अभी खुद विपक्ष में ही हर किसी को भरोसा नहीं है कि गलबहियां लंबे समय तक चलेगी या नहीं। कर्नाटक में अच्छा फोटो शूट हुआ था जिसमें सोनिया व राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती के साथ-साथ शरद यादव भी दिखे थे जिन्हें अभी खुद का ठिकाना नहीं है। वह खुद ही किसी दूसरे का कंधा तलाश रहे हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी भी थे जिनका हमेशा से मानना रहा है कि चुनाव पूर्व गठबंधन संभव ही नहीं है। यानी चाहत तो है कि भाजपा की शक्ति से निपटने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लें, लेकिन हाथ जलने का डर भी है, क्योंकि इनमें से कई दल एक दूसरे के साथ जिंदा नहीं रह सकते। अब सिर्फ केरल में सिमटी माकपा आखिर कांग्रेस के साथ आए तो कैसे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पश्चिम बंगाल जाकर तृणमूल का समर्थन करें भी तो क्या। कुमारस्वामी उत्तर प्रदेश आएं या न आएं इससे अखिलेश यादव व मायावती को क्या लेना देना। और सबसे बड़ी बात कि पूरे क्रम में कांग्रेस या राहुल के हाथ क्या लगना।

इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के प्रबंधन कौशल का भारतीय राजनीति में फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इस सच्चाई से भाजपा भी अनजान नहीं होगी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आगामी चुनाव बहुत अहम साबित होंगे। इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। राजस्थान में जहां प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा पिछले उपचुनावों में दिखा है वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में पंद्रह साल की एंटी इनकबैंसी न हो, यह नहीं माना जा सकता है। इन राज्यों से लोकसभा में फिलहाल भाजपा को नब्बे से सौ फीसद तक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। प्रकृति का नियम तो यह है कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद धारा नीचे आती है। विपक्ष में अस्तित्व को लेकर जो भय है और विश्वास जिस तरह डिगा है उसमें इसकी भी पूरी गुंजाइश है कि वे एक साथ खड़े हों। आखिर मायावती ने भी हाल में सपा के साथ मंच पर आना स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। यह याद रखना होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के बावजूद भाजपा को महज 31 फीसद वोट ही मिले थे। यही कारण है कि शाह की ओर से संगठन की बैठकों में बार-बार 50 फीसद की लड़ाई की बात कही जा रही है। देखना यह होगा कि इस बार कौन सी लहर पैदा होगी जिसमें विपक्ष पूरी तरह बह जाएगा।

(लेखक दैनिक जागरण में सीनियर एक्जीक्यूटिव एडिटर हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

सूचना से इन्कार

चुनाव आयोग की इस राय से राजनीतिक दल उत्साहित हो सकते हैं कि वे सूचना अधिकार कानून के दायरे में नहीं आते, लेकिन यह आदर्श स्थिति नहीं। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग अपने एक फैसले में यह स्पष्ट कर चुका है कि सभी राष्ट्रीय दल इस कानून के तहत आते हैं। यह ठीक नहीं कि राजनीतिक दलों ने उक्त फैसले को चुनौती भी नहीं दी और उस पर अमल करने से भी इन्कार किया। यह तो एक तरह की मनमानी ही है। यदि राजनीतिक दलों को यह लगता है कि केंद्रीय सूचना आयोग का फैसला सही नहीं था तो फिर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत या तो इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए थी या फिर उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए था। चूंकि चुनाव आयोग की टिप्पणी केंद्रीय सूचना आयोग के विपरीत है इसलिए बेहतर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निस्तारण करे। वैसे इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक समय खुद सुप्रीम कोर्ट ने वही रवैया अपनाया था जो राजनीतिक दलों ने अपना रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद को सूचना अधिकार कानून से बाहर रखने के लिए मुकदमेबाजी भी की थी। यह अजीब बात है कि हर कोई जवाबदेही और पारदर्शिता की बातें तो करता है, लेकिन खुद इनसे बचने की फिराक में रहता है। इसी प्रवृत्ति के चलते सूचना अधिकार कानून पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हो पा रहा है। आमतौर पर इस कानून के दायरे में आने वाली संस्थाएं सामान्य जानकारी देने से भी बचती हैं। यही नहीं कभी-कभी तो वे सूचना मांगने वालों को ही परेशान करने में लग जाती हैं।

राजनीतिक दल इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि सूचना अधिकार कानून भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को दूर करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। एक समय कई घपले-घोटाले सूचना अधिकार कानून के जरिये ही सामने आए थे। जब आवश्यकता इस बात की थी कि राजनीतिक दल और विशेष रूप से सत्ता संचालित कर रहे दल अपने आचार-व्यवहार से सूचना अधिकार कानून को प्रभावी बनाने का कार्य करते तब उन्होंने उससे अपने को पूरी तरह अलग कर लिया। सबसे खराब बात यह हुई कि उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। राजनीतिक दल स्वयं को सूचना अधिकार कानून से परे रखने के लिए चाहे जो तर्क दें उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों के तर्क कुल मिलाकर लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के विपरीत हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों को यह शोभा नहीं देता कि वे सूचना अधिकार कानून से बचने के जतन करें। यह सही है कि राजनीतिक दलों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे अपनी हर गतिविधि और फैसलों के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करें, लेकिन कम से कम उन्हें अपने आय-व्यय के बारे में तो पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी ही चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसा करने से बच रहे हैं और अपने रवैये को उचित भी ठहरा रहे हैं। अपने आय-व्यय के बारे में राजनीतिक दलों का यह कहना अर्धसत्य ही है कि वे अपने खातों की जानकारी आयकर विभाग को उपलब्ध कराते हैं या फिर चुनावी बांड के चलन ने राजनीति में कालेधन की भूमिका खत्म कर दी है।

शाबाश बेटियों

यह सुखद है कि कई वर्षों की तरह इस बार भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्राओं ने मेरिट लिस्ट में अपना दबदबा बनाए रखा है। आज के दौर में लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसकी मुख्य वजह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पर विशेष तौर पर फोकस किया है। चाहे उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं हों या सीआइएससीई की, छात्राओं ने अपने परिणाम से सबका ध्यान खींचा है। सीबीएसई में इस बार 71.47 फीसद छात्र व 81.65 फीसद छात्राएं सफल हुई हैं। यानी छात्रों की तुलना में दस फीसद छात्राएं अधिक उत्तीर्ण हुईं। नोएडा की मेघना को 500 में से 499 और गाजियाबाद की अनुष्का को मिले 500 में से 498 नंबर तो मील के पत्थर हैं। यह दर्शाता है कि छात्राएं परीक्षाओं को किस गंभीरता से ले रही हैं।

> मेरिट में आने वाली छात्राओं के सपने भी बड़े हैं और इसे साकार करने के लिए जूझने का माद्दा भी उनमें है

मेरिट में आने वाली छात्राओं के सपने भी बड़े हैं और इसे साकार करने के लिए जूझने का माद्दा भी उनमें है, लेकिन उत्तर प्रदेश रीजन में रिजल्ट प्रतिशत में कमी ने गंभीर सवाल भी उठाए हैं। रिजल्ट में पिछले वर्ष की अपेक्षा 1.01 प्रतिशत की गिरावट आई है जो यह बताती है कि जहां दक्षिण के कालेजों ने अपनी साख समग्र रूप में बरकरार रखी है, वहीं प्रदेश में कुछ कालेजों का स्तर गिर रहा है। सीबीएसई की इंटर परीक्षा में सबसे ज्यादा तिरुअनंतपुरम के 97.32 प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली है। चेन्नई के 93.87 प्रतिशत और दिल्ली में 89 फीसदी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। निश्चित तौर पर उप्र में कालेजों का स्तर बढ़ाने के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि कई कालेजों का स्तर नीचे आने के पीछे मनमाने ढंग से मान्यता बांटा जाना भी है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान क्या विपक्ष ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है?

आज का सवाल

क्या इस बार आइपीएल लोकप्रियता की कसौटी पर खरा उतरा है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें

Y –हां, N–नहीं, C–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आधी बिसात की लड़ाई में पूरा दम

आशुतोष झा

भाजपा ने चुनाव की तैयारी दो वर्ष पहले ही शुरू कर दी थी। विपक्ष को यह आंकना होगा कि वह कितने कदम चल पाया है

चुनावी बिसात बिछ चुकी है। विपक्ष में जश्न का प्रदर्शन हो रहा है कि ऐसे वक्त पर भाजपा के खिलाफ मोर्चे का आधार बनने लगा है जब राजग खेमे में हलचल है। शिवसेना अलग होने की घोषणा कर चुकी है और टीडीपी नाता तोड़ चुकी है। बिहार में सहयोगी जदयू फिर से विशेष राज्य के नारे को धार देने लगा है तो कुछ अन्य छोटे दलों की ओर से बार-बार याद दिलाया जा रहा है कि उनके साथ संवाद कम हो रहा है। इन राजनीतिक घटनाओं के बावजूद अगर भाजपा नेतृत्व की ओर से बार-बार पहले से भी बड़े जनादेश का दावा किया जा रहा है तो उसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता है। बल्कि विपक्ष को भी सतर्क हो जाना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि शतरंज की बाजी बहुत पहले से बिछी है और विपक्ष अपने कई दांव गंवा चुका है। आधी बाजी खत्म होने के बाद मैदान में उतरना तभी सार्थक होगा जब बाकी बचे हर दांव पर पूरे अधिकार के साथ जीत हो। जिस तरह भाजपा का भौगोलिक और सामाजिक विस्तार हुआ है और भाजपा अध्यक्ष उतने भर से संतुष्ट नहीं है, उसका साफ संकेत है कि अगला एक साल क्या रंग दिखाएगा। अगली संसद में बहुमत की लड़ाई अबकी जनता के बीच आधे से ज्यादा मत की लड़ाई होगी। भाजपा ने इसकी तैयारी दो वर्ष पहले ही शुरू कर दी थी। विपक्ष को यह आंकना होगा कि वह कितने कदम चल पाया है।

गणित की तरह चुनाव की विवेचना करें तो सब कुछ साफ-साफ दिखता है। पिछले लोकसभा चुनाव में 17 करोड़ से कुछ ज्यादा वोटरों ने भाजपा का साथ दिया और पार्टी सत्ता में आ गई। 2009 के मुकाबले देखें तो कांग्रेस या दूसरे दलों के वोट में ज्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन मोदी प्रभाव ने भाजपा के खाते में लगभग नौ करोड़ नए वोटर जोड़ दिए। लगभग इसी संख्या में नए वोटरों की संख्या बढ़ी थी। अगली लड़ाई भी इसी मापदंड और रणनीति पर लड़नी होगी। एक रोचक तथ्य और है कि कुल वोटर और मत डालने वाले वोटरों में लगभग 30 करोड़ का अंतर देखा जा रहा है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के बावजूद घटता-बढ़ता मतदान फीसद बहुत कुछ असर दिखाएगा। यह नेतृत्व का असर होगा कि कितने वोटर सक्रिय होते हैं। इस गणित पर विपक्ष की कितनी नजर है? और क्या अब तक कोई विपक्षी दल इसे साधने की कोशिश करता दिखा? इसका जवाब भी उन्हें ही देना होगा, लेकिन एक नजर भाजपा पर डालें- लगभग दो वर्ष पहले भाजपा मुख्यमंत्रियों की बैठक में गरीब कल्याण योजना के बाबत एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। दो तीन भाजपा मुख्यमंत्रियों के साथ संगठन के कुछ लोगों को जोड़ा गया और तय हुआ कि कम से कम भाजपा और राजग शासित राज्यों में गरीबों की हर योजना संवेदनशील तरीके से लागू हो। देश में लगभग 22 करोड़ गरीब परिवार हैं। वहीं भाजपा व राजग शासित राज्यों की संख्या 21 है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा का पूरा जोर इस पर है कि जनता समाज की संवेदनशीलता में आए बदलाव को महसूस करे।

इसके दो तरीके हैं और बचे हुए वक्त में दोनों का इस्तेमाल हो तो अचरज नहीं। एक तरीका था नोटबंदी का। एक छोटे वर्ग को इसने सींखचे में कस दिया था, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग खुश था। जनता को योजनाओं के महत्व का अहसास तब हो जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसका एक उदाहरण भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में मिला था जब प्रधानमंत्री ने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा था पीड़ित परिवारों को बीमा की राशि तत्काल मिलनी चाहिए। अब भाजपा का पूरा अभियान इस पर केंद्रित है कि बिजली, जीवन सुरक्षा बीमा, बच्चों के टीकाकरण जैसी सात अहम योजनाएं हर गांव के हर घर तक पहुंचें। गरीब परिवार की ओर से आवेदन लिखवाने से लेकर दफ्तर से उस पर मुहर लगवाने और घर तक बल्ब पहुंचाने का जिम्मा भाजपा कार्यकर्ताओं ने उठा लिया है। पचास फीसद वोट की इस लड़ाई में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सामने एक बड़ी लकीर कई वर्षों से खींची जा रही है। विपक्ष के एक दो बड़े चेहरे जो अलग-अलग राज्यों में हैं, उन्हें खासतौर पर अपना बहीखाता दिखाना होगा। दलित हो या आदिवासी या अगड़ी जाति का गरीब उसकी जरूरतें एक सी हैं। पांच लाख रुपये तक के इलाज की आयुष्मान योजना भी इसी का अंग है। एक बड़ी कमी अभी भी बची है वह है पुलिस सुधार। दरअसल लगभग सत्तर अस्सी फीसद मामलों में जनता के रोष का कारण पुलिस होती है। अधिकतर राज्यों मे भाजपा की सरकारें हैं और पार्टी के अधिकतर सांसद भी यहीं से चुनकर आते हैं।

अब नजर इस पर है कि बचे हुए साल में मोदी सरकार के पिटारे में क्या-क्या हो सकता है। राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद मोदी साहसिक व जोखिम भरे कदम उठाते रहे हैं। क्या आगे भी वह कुछ कड़वी दवा दे सकते हैं? फिलहाल इसकी उम्मीद कम दिखती है। हां, वह मध्यम वर्ग जरूर राहत का अहसास कर सकता है जो पचास फीसद की लड़ाई में मजबूती दे। और यह मध्यमवर्ग अक्सर आयकर व दूसरे करों की दृष्टि से ही सोचता है। रोजगार या स्वरोजगार की बहस के बीच आने वाला साल कुछ नई पहल ला सकता है।

पर यह भाजपा भी जानती है और विपक्षी पार्टियां भी कि सभी मुद्दों के ऊपर आखिर में नेतृत्व ही आता है। भारतीय जनमानस ही कुछ ऐसा है कि वह स्वाभिमान के साथ आधे पेट सो सकता है। भाजपा की पहचान राष्ट्रवादी रही है और आने वाला साल खासकर आतंक या आतंकियों को लेकर कोई संदेश दे सकता है। चुनावी राजनीति में गठबंधन अहम होता है और हाल के कर्नाटक चुनाव ने इसे फिर से साबित किया है, लेकिन गणित दुरुस्त करने के लिए आपसी व जनता के साथ संबंधों का रसायन भी सटीक होना जरूरी है। फिलहाल इस रसायन पर काम करती सिर्फ भाजपा दिख रही है।

(लेखक दैनिक जागरण में राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मित्रता

प्रेम बहुत सेलेक्टिव (चयनात्मक) होता है, क्योंकि उसका केंद्र और आधार ही राग होता है। मैत्री प्रेम का विस्तार है। जब तक आपके प्रेम का दायरा न फैले, आप किसी के मित्र हो ही नहीं सकते और न कोई आपका मित्र हो सकता है। मित्रता का अर्थ ही है-दूसरे के सान्निध्य का मजा लेना और उसके प्रति सम्मान का भाव रखना। मैत्री में दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव होता है। यह निर्जीव वस्तुओं तक के प्रति हो सकती है। मैत्री के इस फैलाव का ही परिणाम होगा कि पंचतंत्र में 5 में से दो अध्यायों-मित्रलाभ और मित्रभेद को मैत्री को समर्पित किया गया। यह दुनिया तभी तक प्यारी है, जब तक कोई आपको अपना कहता है और मित्र से बढ़कर अपनत्व का भाव किसमें होता है? मैत्री दो लोगों के बीच का पारस्परिक मेल मात्र नहीं होती। यह एक पारस्परिक बंधन भी होता है। इसलिए जीवन का यह किला मैत्री से मजबूत होता है। मित्रता करना और मित्र पाना इंसान के जीवन का सबसे महान सुख है। आपका मित्र आपके लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। आप भी उसके प्रति विश्वास की भावना रखेंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि किसी के लिए विश्वसनीय बनकर ही उसका विश्वासपात्र बना जा सकता है। जो मित्र होगा, आप भी उसके सान्निध्य की इच्छा लिए रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का जब सान्निध्य मिले और उस क्षण में आपको समय का बोध न रह जाए तो समझिए कि आप एक सच्चे मित्र की संगति में हैं।

ज्ञानयोग का आधार मैत्री ही है। बुद्ध ने अगला अवतार मैत्रेय के रूप में लेने का उद्घोष कर मित्रता को बड़ी गरिमा प्रदान की। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो ऐसे संबंध को अशुद्ध लौकिक मैत्री कहेंगे, लेकिन अगर आप किसी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो यह शुद्ध लौकिक मैत्री कहलाएगी। ऐसे ही, अशुद्ध मैत्री में गुरु का सम्मान तो होता है, किंतु व्यक्ति स्वयं आत्म-विस्मरण में जीता है। शुद्ध मैत्री वह है जिसमें गुरु का सम्मान हो और आत्म-स्मरण भी बना रहे। शुद्ध मैत्री में व्यक्ति गुरु की कृपा अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करता है। अगर आत्मविस्मरण के साथ विराट से मैत्री हो तो वह अशुद्ध परामैत्री है। उसमें शुद्धता तब आती है जब व्यक्ति आत्मस्मरण के साथ उस विराट के प्रति मैत्रीभाव में जीता है और परमात्मा की कृपा सदैव महसूस करता है।

श्री ओशो सिद्धार्थ

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

तेजी से बदलता सियासी परिवेश

मोदी की उपलब्धियां और चुनौतियां शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. एके वर्मा ने मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल पर प्रकाश डाला है। 1951-52 में जब पंचवर्षीय योजना को हरी झंडी दी गई थी, तब उस पर विनोबा भावे ने कहा था कि सरकार की सभी राष्ट्रीय योजनाओं का मकसद रोजगार बढ़ाना भी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनाव में देश के हर वर्ग के अच्छे दिन लाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हुए सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन उनके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो पलक झपकते ही देश की हर समस्या का हल निकल जाए। बेशक मोदी ने आर्थिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए नोटबंदी और जीएसटी के कड़वे फैसले लिए और विदेशों सें संबंध मजबूत करने के लिए खूब विदेशों की यात्राएं भी कीं, लेकिन मोदी सरकार महंगाई, जिसमें मुख्यतः पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी उछाल, बेरोजगारी, पाकिस्तान की नापाक हरकतों और नक्सलवाद पर लगाम कसने में नाकाम ही सिद्ध हुई है। 2019 का अगर भाजपा को चुनाव जीतना है तो उसे अभी से ही हर राज्य में, वहां चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, आमजन के आधार से जुड़े मुद्दों की तरफ ध्यान देना होगा। अंत में यह भी कहना उचित होगा कि भाजपा जब से अस्तित्व में आई है, तब से बेशक कारवां बढ़ता गया, लेकिन भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के सिवाय दूसरा ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको आगे करके आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार में पेश किया जाए, अगर होता तो प्रधानमंत्री को देश के हर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना पड़ता।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

बढ़ती गर्मी

मई के इस महीने में बरस रही आग लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर रही है। गर्मी की यह तपिस भारत ही नहीं विदेशों तक महसूस की जा रही है। वहां के लोग भी प्रचंड गर्मी को झेलने को मजबूर हैं। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये गर्मी इतनी क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण ग्लोबल वॉर्मिंग है। दुनिया के देशों को इस पर मंथन करना चाहिए। यह किसी एक देश की समस्या नहीं है, सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी इससे निजात मिल सकेगी।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

खस्ताहाल बैंक

हम दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हमारे बैंकों की हालत खस्ता हो रही है। बैंकिंग घोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद भले ही सरकार और आरबीआई बैंकों की स्थिति सही होने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में बैंकों की स्थिति इस तरह खराब हो चुकी है कि वो दिन ब दिन कर्जो में डूबते जा रहे हैं। आम जनता के टैक्स के पैसे को विकास कार्यों में लगाने के बजाए बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। समय रहते अगर इन बैंकों की स्थिति नहीं सुधरी तो निश्चय ही हमारी बैंकिंग प्रणाली ठप हो जाएगी।

नीरज झा, दिल्ली विवि

विपक्ष का गठबंधन

कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार के शपथ समारोह में बड़े जोर-शोर से भाजपा के खिलाफ एकत्रित होकर सारे विपक्षियों ने 2019 का बिगुल बजाया। कहीं उनकी एकता सिर्फ शपथ ग्रहण तक ही सिमट कर ना रह जाए. क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी बहुमत आने पर पहले ही प्रधानमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। इधर मायावती, मुलायम सिंह, चंद्रबाबू नायडू भी पीएम बनने को आतुर हैं। विपक्षी दलों में अभी से ही पीएम कौन की लड़ाई शुरू हो गई है। आगे चलकर ये क्या करेंगे? mahesh_nenava@yahoo.com

बेरोजगारी का दंश

आज देश में सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई बेरोजगारी है। जनसंख्या बढ़ रही है। युवाओं की बड़ी फौज खड़ी होती जा रही है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। देश का ज्यादातर युवा नौकरी की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन जिस अनुपात में युवा हैं, उसके हिसाब से नौकरियां नहीं हैं। जब भी किसी पद के लिए आवेदन मांगे जाते हैं तो आवेदकों की भारी संख्या यह बताने के लिए काफी है कि समस्या कितनी विकराल है। इस समस्या का मूल शिक्षा पर आधारित है और ऐसा भी नहीं है कि सरकारों ने इस ओर कुछ काम नहीं किया। लेकिन अभी भी आधुनिक शिक्षा से प्रत्येक घर जुड़ नहीं पाया है। कुछ व्यवसायी शिक्षा इतनी महंगी है कि आम युवा की पहुंच से बहुत दूर है। यहां पर बढ़ती हुई जनसंख्या की भी हम अनदेखी नहीं कर सकते। हालांकि इसी युवा शक्ति के दम पर हम दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की उम्मीद करते हैं। अगर हमें ऐसा करना है तो इस ओर एक बड़ी कार्य योजना बनाकर निर्माण क्षेत्र में उतरना होगा और साथ ही निर्यात को आसान बनाना होगा। क्योंकि हमारा पड़ोसी चीन इसी तकनीक के दम पर आज एक ऐसा उत्पादक बन गया है जिसका माल दुनिया के हर कोने में बिक रहा है। बहरहाल जब तक हम अपनी युवा ऊर्जा शक्ति का सही जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक लंबी होती जॉब की कतार छोटी नहीं हो पाएगी। इसके लिए रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। वर्तमान सरकार ने इसी समस्या के समाधान के लिए बड़ी संख्या में कौशल विकास केंद्र खोलने की योजना बनाई थी। कुछ केंद्र खुले भी हैं, लेकिन उनका परिणाम सामने नहीं आ सका है। रोजगारपरक शिक्षा ऐसी हो जो हर एक की पहुंच में हो और कम समय में उसे प्राप्त करने के बाद रोजगार हासिल किया जा सके, तभी इस समस्या से निजात मिल सकेगी।

शैलेंद्र सिंह, भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली

ट्वीट-ट्वीट

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे उद्घाटन के दौरान 45 डिग्री की इस गर्मी में लोग न सिर्फ नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचे हैं, बल्कि सरकार की उपलब्धियां सुनकर जिस उत्साह से नारे लगा रहे हैं उससे एसी कमरे में भी विपक्ष के पसीने छूट रहे होंगे।

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

कांग्रेस और जद-एस ने कर्नाटक में भाजपा को मात दे दी। अच्छी बात है, लेकिन अब कर्नाटक में जल्दी से कैबिनेट का गठन नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी एक हफ्ते की छुट्टी पर हैं। इसमें नुकसान जनता का ही होगा।

डीपी सतीश@dp_satish

एक सिख पुलिस अधिकारी ने मुस्लिम युवा की जान बचाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है? मैं इसी तरह का भारत चाहता हूं और हमेशा ऐसा चाहूंगा भले ही ऐसा चाहने वाला मैं इकलौता शख्स ही क्यों न बचूं।

चेतन भगत@chetan_bhagat

कश्मीर के प्रमुख अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की बेटी ने जम्मू-कश्मीर में सीबीएसई बोर्ड की बारहवीं कक्षा में पूरे राज्य में टॉप किया है। वहीं कश्मीर में गरीब बच्चियों को स्कूल छोड़कर सड़कों पर पत्थरबाजी के लिए उकसाया जाता है। वहां लोगों के लिए नियम भी अलग-अलग हैं।

मेजर गौरव आर्या@majorgauravarya

जनपथ

बिगड़े-बिगड़े लग रहे माया जी के बोल,
इतनी जल्दी फट गया कर्नाटक का ढोल।
कर्नाटक का ढोल सीट का हो बंटवारा,
तब होगा चरितार्थ एकता वाला नारा।
जनपद-सूबा-गांव हर तरफ अगड़े-पिछड़े,
मिले न जिनको सीट समझिए तेवर बिगड़े।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 313